



Daily करेंट अफेयर्स

➤ 22 अगस्त 2025

NATIONAL AFFAIRS

1. भारत सरकार ने वित्त वर्ष 35 तक 97 गीगावाट कोयला और लिग्नाइट आधारित विद्युत क्षमता जोड़ने का संशोधित लक्ष्य रखा।



अगस्त 2025 में, केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने राज्यसभा (संसद के ऊपरी सदन) में एक लिखित उत्तर में घोषणा की कि भारत सरकार (GoI) ने वित्तीय वर्ष 2034-35 (FY 35) तक अतिरिक्त 97 गीगा वाट (GW) कोयला और लिग्नाइट आधारित बिजली उत्पादन क्षमता जोड़ने के अपने लक्ष्य को संशोधित किया है, जो कि वित्त वर्ष 32 तक 90 गीगावाट के पहले के प्रक्षेपण से अधिक है।

- संशोधित लक्ष्य का लक्ष्य वित्त वर्ष 35 तक कुल 307 गीगावाट कोयला और लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत स्थापित क्षमता प्राप्त करना है। यह संशोधन भारत सरकार के अद्यतन बिजली मांग अनुमानों और स्वच्छ ऊर्जा विस्तार के साथ ऊर्जा सुरक्षा के संतुलन की आवश्यकता को दर्शाता है।

- यह कोयला क्षमता वृद्धि भारत के बड़े ऊर्जा रोडमैप के अनुरूप है, जो 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा (RE) क्षमता और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। थर्मल पावर विस्तार एक स्थिर स्रोत के रूप में काम करेगा जबकि आरई क्षमता बढ़ेगी।

- इससे पहले, भारत सरकार ने अनुमान लगाया था कि वित्त वर्ष 32 तक लगभग 283 गीगावाट कोयला और लिग्नाइट-आधारित क्षमता की आवश्यकता होगी। नवंबर 2023 में, विद्युत मंत्रालय (MoP) ने वित्त वर्ष 32 तक न्यूनतम 80 गीगावाट अतिरिक्त कोयला-आधारित तापीय क्षमता स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे अब वित्त वर्ष 35 तक संशोधित करके 97 गीगावाट कर दिया गया है।

Key Points:-

(i) जून 2025 तक, भारत की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 485 गीगावाट है, जिसमें कोयला, लिग्नाइट, जलविद्युत, गैस, परमाणु ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। ताप विद्युत अभी भी सबसे बड़ा योगदान देती है, जिससे यह भारत की आधारभूत मांग की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है।

(ii) राष्ट्रीय विद्युत योजना (NEP) 2023 (उत्पादन) के अनुसार, भारत की कुल स्थापित क्षमता वित्त वर्ष 32 तक 874 गीगावाट तक पहुँचने की उम्मीद है। इस विस्तार में नवीकरणीय और तापीय ऊर्जा दोनों शामिल हैं, जो सतत विकास के लिए भारत की "ऊर्जा मिश्रण" रणनीति को दर्शाता है।

2. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने IT 2.0 - उन्नत डाक प्रौद्योगिकी (APT) के राष्ट्रव्यापी रोलआउट की घोषणा की।



अगस्त 2025 में, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ने भारतीय डाक के अंतर्गत उन्नत डाक प्रौद्योगिकी (APT) को देश भर में लागू करने की आधिकारिक घोषणा की। 5,800 करोड़ रुपये की यह परियोजना, ग्राहक-केंद्रित डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण और संवर्धन हेतु भारत के सूचना प्रौद्योगिकी (IT) 2.0 कार्यक्रम का एक हिस्सा है।

- IT 2.0 - APT कार्यक्रम संचार मंत्रालय (MoC) के तहत 5,800 करोड़ रुपये का निवेश है, जिसे पूरे भारत में तेज, स्मार्ट और अधिक कुशल डाक संचालन को सक्षम करके प्रोजेक्ट आईटी 1.0 के निर्माण के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- इस प्रणाली को डाक विभाग (DoP), MoC के अंतर्गत कार्यरत डाक प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र (CEPT) द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। यह डाक क्षेत्र में तकनीकी आत्मनिर्भरता पर भारत के बढ़ते जोर को दर्शाता है।

Key Points:-

(i) APT को भारत सरकार (GoI) के मेघराज 2.0 क्लाउड प्लेटफॉर्म पर होस्ट किया गया है और भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) द्वारा समर्थित है, जो राष्ट्रव्यापी संचालन के लिए सुरक्षित, स्केलेबल और विश्वसनीय डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करता है।

(ii) IT 2.0 की प्रमुख विशेषताओं में एकल एकीकृत उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस, QR कोड-आधारित भुगतान, वन टाइम पासवर्ड (OTP)-सक्षम डिलीवरी और डाक लेनदेन में सटीकता, सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 10-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर (DIGINP) शामिल हैं।

(iii) IT 2.0-APT का क्रियान्वयन 23 डाक सर्किलों में चरणों में किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत कर्नाटक में पायलट प्रोजेक्ट (मई-जून 2025) से होगी और 4 अगस्त 2025 तक पूरे देश में पूरा कर लिया जाएगा, जिसमें भारत के 1.70 लाख से अधिक डाकघर शामिल होंगे।

3. IIT मद्रास और FedEx ने चेन्नई में AI-संचालित लॉजिस्टिक्स समाधान के लिए स्मार्ट सेंटर का शुभारंभ किया।



अगस्त 2025 में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (IIT-M) ने अग्रणी अमेरिकी परिवहन कंपनी फेडरल एक्सप्रेस कॉर्पोरेशन (FedEx) के सहयोग से, चेन्नई, तमिलनाडु स्थित IIT-M परिसर में FedEx स्मार्ट सेंटर (आपूर्ति श्रृंखला मॉडलिंग, एल्गोरिदम, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी केंद्र) का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से संचालित, टिकाऊ लॉजिस्टिक्स समाधानों को आगे बढ़ाना है।

- FedEx स्मार्ट सेंटर को FedEx से 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 44 करोड़ रुपये) की 5-वर्षीय वित्तीय सहायता प्राप्त है। यह वित्तीय सहायता IIT मद्रास के शोधकर्ताओं और छात्रों को उद्योग विशेषज्ञों के साथ मिलकर लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन के लिए उन्नत तकनीकी समाधान तैयार करने में सक्षम बनाएगी।

- केंद्र का मुख्य कार्य उन्नत डिजिटल उपकरण, एल्गोरिथम-आधारित अनुसंधान और उद्योग ज्ञान को एकीकृत करना है ताकि ऐसे लॉजिस्टिक्स नेटवर्क डिजाइन किए जा सकें जो लचीले, लचीले और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ हों।

- यह विभिन्न क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला संचालन में दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

Key Points:-

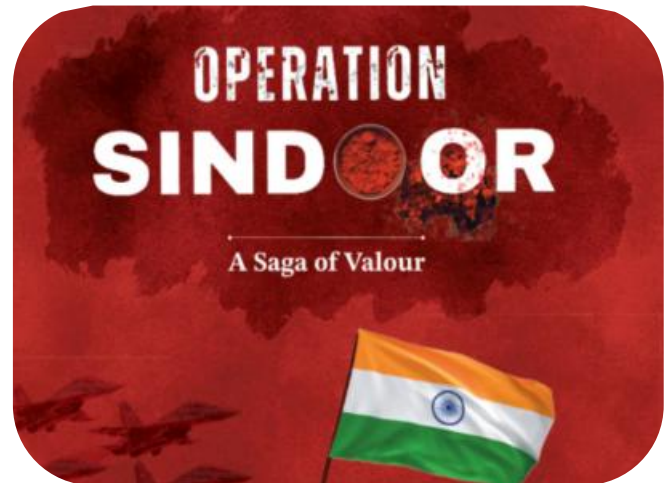
(i) SMART सेंटर के प्रमुख अनुसंधान क्षेत्रों में कार्बन-तटस्थ संचालन का विकास, रसद के लिए AI-संचालित पूर्वानुमान विश्लेषण, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) अवसंरचना एकीकरण, स्वायत्त वितरण प्रणालियाँ और AI-संचालित श्रमिक सुरक्षा प्रणालियाँ शामिल हैं। ये क्षेत्र भारत के सतत विकास और तकनीकी उन्नति के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप हैं।

(ii) इस केंद्र की स्थापना से अनुप्रयुक्त अनुसंधान और नवाचार में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में IIT मद्रास की स्थिति मज़बूत होगी। लॉजिस्टिक्स में फेडेक्स की अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता और IIT मद्रास की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ, इस साझेदारी से आपूर्ति श्रृंखलाओं की चुनौतियों के लिए परिवर्तनकारी समाधान मिलने की उम्मीद है, खासकर दुनिया भर में टिकाऊ और डिजिटल-प्रथम लॉजिस्टिक्स प्रणालियों की बढ़ती माँग के संदर्भ में।

(iii) इस केंद्र को शुरू करके, IIT मद्रास और FedEx का लक्ष्य एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में योगदान करना है जहाँ प्रौद्योगिकी, नवाचार

और स्थिरता भारत और उसके बाहर रसद के भविष्य को फिर से परिभाषित करने के लिए एक साथ काम करते हैं।

4. NCERT ने कक्षा 3-12 के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर शैक्षिक मॉड्यूल लॉन्च किया।



अगस्त 2025 में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने कक्षा 3 से 12 तक के छात्रों को पहलगाम आतंकवादी हमले के प्रति भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया, ऑपरेशन सिंदूर, के बारे में शिक्षित करने के लिए दो शैक्षिक मॉड्यूल शुरू किए। ये मॉड्यूल सैन्य सफलता, उन्नत तकनीक और राष्ट्रीय सुरक्षा जागरूकता पर प्रकाश डालते हैं।

- ऑपरेशन सिंदूर, 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में मई 2025 में शुरू किया गया था, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे। इस हमले में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में स्थित आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया गया था, जिसका समन्वय लश्कर-ए-तैयबा ने किया था और जिसकी योजना भारतीय सशस्त्र बलों से प्राप्त खुफिया जानकारी के आधार पर बनाई गई थी।

- NCERT ने दो मॉड्यूल बनाए: कक्षा 3-8 के लिए "ऑपरेशन सिंदूर - वीरता की एक गाथा" जिसमें युवा शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए कहानियों

और गतिविधियों का उपयोग किया गया है, और कक्षा 9-12 के लिए "ऑपरेशन सिंदूर - सम्मान और बहादुरी का एक मिशन" जिसमें रणनीति, निष्पादन और परिचालन परिणामों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

● ये मॉड्यूल भारत की रक्षा क्षमताओं को उजागर करते हैं, जिसमें दुश्मन के ड्रोन और विमानों को निष्क्रिय करने वाली एस-400 वायु रक्षा प्रणाली भी शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर ने नागरिक हताहतों से बचते हुए आतंकवादी ढाँचों पर सटीक हमले किए, जो भारत की उन्नत सैन्य तकनीक और रणनीतिक योजना को दर्शाता है।

Key Points:-

(i) ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक राजनीतिक संदेश के रूप में कार्य किया, जिसने सीमा पार आतंकवाद के विरुद्ध भारत के कड़े रुख को दर्शाया। इसने राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पुष्ट किया, कूटनीतिक विश्वसनीयता को मज़बूत किया और वैश्विक मंच पर सक्रिय रक्षा एवं आतंकवाद-रोधी उपायों को उजागर किया।

(ii) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप, ये मॉड्यूल वास्तविक दुनिया की घटनाओं को पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं, जिससे आलोचनात्मक सोच, राष्ट्रीय गौरव और सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा मिलता है। छात्र अनुभवात्मक शिक्षा और ऐतिहासिक विश्लेषण के माध्यम से भारत की भू-राजनीतिक चुनौतियों, सैन्य नैतिकता और राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा के महत्व को सीखते हैं।

(iii) पाठ्यक्रम के आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय जागरूकता बढ़ाने के लिए इन मॉड्यूल को शिक्षकों और नीति निर्माताओं से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। हालाँकि विषयवस्तु को लेकर कुछ राजनीतिक बहसें हुईं, फिर भी NCERT भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाओं पर मॉड्यूल बनाने की योजना बना

रहा है, जिसका उद्देश्य छात्रों की भारत की रक्षा और भू-राजनीतिक प्राथमिकताओं की समझ को गहरा करना है।

5. केंद्र ने भगवान परशुराम का सम्मान करते हुए उत्तर प्रदेश में जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने को मंजूरी दे दी।



अगस्त 2025 में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर ज़िले के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर "परशुरामपुरी" करने को मंजूरी दे दी। यह परिवर्तन भगवान विष्णु के छठे अवतार, भगवान परशुराम के सम्मान में है और उनकी जन्मभूमि के रूप में इस क्षेत्र के पौराणिक महत्व को दर्शाता है।

● स्थानीय ग्रंथ और धार्मिक परंपराएँ जलालाबाद को हिंदू पौराणिक कथाओं में पूजनीय भगवान परशुराम की जन्मभूमि से जोड़ती हैं। सदियों से, यहाँ उनके प्राचीन मंदिर के आसपास तीर्थस्थल और पूजा केंद्र विकसित हुए हैं, जिससे यह शहर इस क्षेत्र में आध्यात्मिक श्रद्धा और सांस्कृतिक विरासत का केंद्र बन गया है।

● नाम परिवर्तन की तैयारी लंबे समय से चल रही थी - जनता की भावना, स्थानीय हिंदू संगठनों, जलालाबाद की नगर परिषद और 2018 और 2023 में पारित कई प्रस्तावों द्वारा समर्थित। इसके बाद

अप्रैल 2025 में जिला मजिस्ट्रेट धर्मेन्द्र प्रताप सिंह की औपचारिक सिफारिशों की गई।

● मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने तुरंत इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। 27 जून, 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने केंद्र को एक आधिकारिक सिफारिश भेजी। राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने भी सार्वजनिक रूप से इसकी सराहना की और इसे समुदाय के लिए गौरव का क्षण बताया।

Key Points:-

(i) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त, 2025 को राज्य के अनुरोध और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से सिफारिश प्राप्त करने के बाद मंजूरी दे दी। MoHA ने अपनी अनापत्ति की सूचना दी, जिससे राज्य को हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया।

(ii) नाम बदलने के साथ, स्थानीय प्रशासन मंदिर परिसर और आसपास के बुनियादी ढाँचे को बेहतर बनाने का इरादा रखता है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, 42 एकड़ के मंदिर के तालाब के सौंदर्यीकरण, मार्ग निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए मुख्यमंत्री विकास योजना और अमृत सरोवर योजना के तहत धनराशि आवंटित की गई है।

(iii) जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने से शहर की स्वदेशी आध्यात्मिक विरासत में निहित पहचान और मज़बूत होने, सांस्कृतिक गौरव और ऐतिहासिक निरंतरता को बल मिलने की उम्मीद है। राजपत्र अधिसूचना जारी होने के बाद, नया नाम आधिकारिक तौर पर नक्शों, सरकारी अभिलेखों और साइनबोर्डों पर अपनाया जाएगा, जो मुगलकालीन नामकरण से एक प्रतीकात्मक बदलाव का प्रतीक है।

INTERNATIONAL

1. भारत और सऊदी अरब ने समुद्री व्यापार, रसद और सतत बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की।



अगस्त 2025 में, भारत के केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और सऊदी अरब के परिवहन और रसद सेवा मंत्री सालेह बिन नासिर अल-जस्सर के बीच एक उच्च स्तरीय आभासी बैठक के बाद, दोनों देशों ने शिपिंग और रसद में समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह के गठन की घोषणा की।

● समुद्री सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह (JWG) की स्थापना रणनीतिक भागीदारी परिषद के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए की गई थी, जिसका उद्देश्य शिपिंग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में केंद्रित नीतिगत वार्ता और बुनियादी ढांचे के सहयोग के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है।

● यह पहल भारत के विदेश मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और सऊदी अरब के विदेश मंत्री सालेह बिन नासिर अल-जस्सर के बीच एक वर्चुअल उच्च-स्तरीय बैठक के बाद हुई। चर्चा के दौरान, दोनों पक्षों ने ऐतिहासिक आर्थिक संबंधों और सामाजिक-सांस्कृतिक अभिसरण को गहन समुद्री जुड़ाव की नींव के रूप में रेखांकित किया।

● सर्बानंद सोनोवाल ने सऊदी अरब की फोक मैरीटाइम सर्विसेज द्वारा नए जेद्दा-मुंद्रा/न्हावा शेवा शिपिंग मार्ग के शुभारंभ पर प्रकाश डाला, जिससे पारगमन समय और लागत में कमी आएगी। उन्होंने निर्बाध समुद्री व्यापार को सुगम बनाने के लिए भारत के मैत्री डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सहयोग का भी प्रस्ताव रखा।

Key Points:-

(i) वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 42 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। समुद्री सहयोग पहल भारत के मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और अमृत काल विजन 2047 को सऊदी विजन 2030 के साथ संरेखित करती है, जिससे रसद, स्थिरता और व्यापार अवसंरचना में सहक्रियात्मक मार्ग उपलब्ध होते हैं।

(ii) भारत ने अपने समुद्री विकास कोष के माध्यम से, जिसकी कुल राशि 3 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है, अपने समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में सऊदी अरब के निवेश को आमंत्रित किया। वधावन बंदरगाह (महाराष्ट्र) और वीओ चिदंबरनार बंदरगाह (तमिलनाडु) में आउटर हार्बर परियोजना जैसी प्रमुख परियोजनाओं को प्रमुख निवेश अवसरों के रूप में प्रस्तुत किया गया।

(iii) इस सहयोग का उद्देश्य हरित हाइड्रोजन हब बंदरगाहों, डिजिटल बंदरगाह संचालन और टिकाऊ शिपिंग समाधानों में संयुक्त उद्यम स्थापित करना है। भारत के ट्रिलियन डॉलर के समुद्री रोडमैप के साथ, यह साझेदारी भविष्य के लिए तैयार, पर्यावरण के प्रति जागरूक समुद्री बुनियादी ढाँचे में निवेश पर ज़ोर देती है।

BANKING & FINANCE

1. एक्जिम बैंक ने निवेश और विकास के लिए ECOWAS बैंक के साथ 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर के क्रेडिट लाइन समझौते पर हस्ताक्षर किए।



अगस्त 2025 में, भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) ने पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय (ECOWAS) की वित्तीय संस्था, ECOWAS निवेश एवं विकास बैंक (EBID) के साथ 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वाणिज्यिक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य भारत-अफ्रीका आर्थिक सहयोग को मज़बूत करना और पश्चिम अफ्रीका में बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का वित्तपोषण करना है।

● इस समझौते पर EBID के अध्यक्ष एवं निदेशक मंडल (BoD) के अध्यक्ष डॉ. जॉर्ज अग्येकुम डोनकोर और एक्जिम बैंक की लंदन शाखा, यूनाइटेड किंगडम (UK) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अशोक कुमार वर्तिया के बीच हस्ताक्षर हुए। यह समझौता अफ्रीकी विकास वित्त संस्थानों के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है।

● इस समझौते का मुख्य उद्देश्य ECOWAS सदस्य देशों में विकासात्मक और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराना है, जिसमें भारतीय कंपनियों की महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। इससे जिन क्षेत्रों को लाभ होने की उम्मीद है उनमें नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और औद्योगिक क्षमता निर्माण शामिल हैं।

● यह ऋण व्यवस्था रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देगी, भारतीय निर्यातकों के लिए नए व्यापार अवसर

खोलेगी और साथ ही अफ्रीकी देशों को सतत विकास हासिल करने में सहायता करेगी। यह अफ्रीका में भारत की व्यापक आर्थिक कूटनीति नीति को भी दर्शाता है।

Key Points:-

(i) EBID के साथ भारत की साझेदारी 2006 से चली आ रही है, जब पहली ऋण सुविधा प्रदान की गई थी। पिछले कुछ वर्षों में, एक्जिम बैंक ने EBID को छह अलग-अलग ऋण सुविधाएँ प्रदान की हैं, जिनका कुल मूल्य 1.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिससे अफ्रीकी देशों द्वारा भारतीय वस्तुओं, मशीनरी और सेवाओं की खरीद संभव हुई है।

(ii) वर्तमान समझौता अफ्रीका में भारत की उपस्थिति को और मज़बूत करता है और दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंधों की नींव पर मज़बूती प्रदान करता है। इससे आपसी विश्वास में वृद्धि, भारत के निर्यात क्षेत्र का विस्तार और ECOWAS देशों को भारत से विश्वसनीय वित्तपोषण के साथ महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

2. पंजाब नेशनल बैंक (PNB) भारत में 'bank.in' डोमेन पर माइग्रेट करने वाला पहला PSB बन गया।



अगस्त 2025 में, भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक (PSB), पंजाब नेशनल बैंक

(PNB), अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट को सुरक्षित 'bank.in' डोमेन पर स्थानांतरित करने वाला पहला भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन जाएगा। यह कदम डिजिटल बैंकिंग में साइबर सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अप्रैल 2025 के परिपत्र के अनुरूप उठाया गया है।

● पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट को पहले के www.pnb.bank.co.in से नए <https://pnb.bank.in> डोमेन पर स्थानांतरित कर दिया है, जिससे यह इस डिजिटल बदलाव को अपनाने वाला पहला भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। यह कदम डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से निपटने के भारत के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

● यह पहल भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के उस निर्देश के बाद शुरू की गई है जिसमें भारतीय बैंकों को अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइटों को नए सुरक्षित 'bank.in' डोमेन में बदलने का निर्देश दिया गया था। RBI ने वित्तीय संस्थानों के लिए एक अधिक सुरक्षित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु अप्रैल 2025 में यह अधिसूचना जारी की थी।

Key Points:-

(i) 'bank.in' डोमेन का एकमात्र रजिस्ट्रार बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान (IDRBT) है, जो डोमेन पंजीकरण, अनुपालन और सुरक्षा उपायों की देखरेख करेगा। इससे यह सुनिश्चित होता है कि केवल अधिकृत भारतीय बैंक ही इस डोमेन का उपयोग कर सकें।

(ii) इस डोमेन माइग्रेशन का मुख्य उद्देश्य साइबर सुरक्षा को मज़बूत करना, फ़िशिंग हमलों के जोखिम को कम करना और डिजिटल बैंकिंग में जनता का विश्वास बढ़ाना है। इसके अलावा, RBI गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के लिए एक समर्पित डोमेन के रूप में 'fin.in' शुरू करने की भी योजना बना रहा है, जिससे पूरे वित्तीय क्षेत्र में एक समान सुरक्षा मानक

सुनिश्चित होंगे।

ECONOMY & BUSINESS

1. भारत का समुद्री मछली उत्पादन 2023-24 में 44.95 लाख टन तक पहुंच गया और इसे PMMSY और जलीय कृषि विकास का समर्थन प्राप्त है।



2023-24 में, भारत का समुद्री मछली उत्पादन प्रभावशाली रूप से बढ़कर 44.95 लाख टन हो गया, जो एक दशक पहले 34.43 लाख टन था, जो समुद्र आधारित मत्स्य पालन में निरंतर वृद्धि को दर्शाता है।

- 1950-51 में केवल 5.34 लाख टन से, भारत का समुद्री मछली उत्पादन 2023-24 में 44.95 लाख टन तक पहुंच गया है, जिसका श्रेय निरंतर निवेश, तकनीकी प्रगति और बेहतर मछली पकड़ने के बुनियादी ढांचे को जाता है।

- एनवीस्टेड्स इंडिया 2025 रिपोर्ट के अनुसार, समुद्री मछली उत्पादन आधारभूत अवधि में 34.43 लाख टन से बढ़कर 2023-24 में 44.95 लाख टन हो गया, जो इस क्षेत्र के ऊपर की ओर बढ़ने और राष्ट्रीय समुद्री खाद्य आपूर्ति में इसके बढ़ते योगदान को रेखांकित करता है।

- जहाँ समुद्री मत्स्य पालन में तेज़ी से वृद्धि हुई है, वहीं तटीय जलीय कृषि, विशेष रूप से झींगा पालन, ने निर्यात में तेज़ी ला दी है। 2013-14 और 2023-24

के बीच अकेले झींगा उत्पादन में लगभग 270% की वृद्धि हुई, जिससे भारत के समुद्री खाद्य निर्यात के आँकड़े बढ़े।

Key Points:-

(i) भारत की 8,118 किलोमीटर लंबी विस्तृत तटरेखा और 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर का विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) 5.31 मिलियन मीट्रिक टन की वार्षिक मत्स्य पालन क्षमता रखता है। इस प्रकार, वर्तमान उपलब्धियों के बावजूद, समुद्री उत्पादन को और बढ़ाने के लिए गहरे समुद्र और उच्च समुद्र में मत्स्य पालन की अभी भी महत्वपूर्ण अप्रयुक्त क्षमता मौजूद है।

(ii) केंद्र सरकार के सहयोग से — विशेष रूप से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) और मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (FIDF) जैसी योजनाओं के तहत — अवसंरचना विकास को बढ़ावा मिला है, जिससे मत्स्य पालन क्षेत्र 2013-14 के 95.79 लाख टन से बढ़कर 2023-24 में लगभग 195 लाख टन हो गया है। पिछले एक दशक में समुद्री मछली उत्पादन भी उल्लेखनीय रूप से दोगुना हो गया है।

2. ICRA ने भारत की Q1FY26 GDP वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान लगाया है, जो RBI के 6.5% पूर्वानुमान से अधिक है।



अगस्त 2025 में, ICRA लिमिटेड (पूर्व में इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड) ने वित्त वर्ष 2025-26 (अप्रैल-जून 2025) की पहली तिमाही के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान लगाया था। इस वृद्धि दर के अनुमान को उच्च सरकारी व्यय और मजबूत निर्यात प्रदर्शन का समर्थन प्राप्त है। यह अनुमान भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के 6.5% के पूर्वानुमान से ज़्यादा है, हालाँकि वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में दर्ज 7.4% की वृद्धि दर से कम है।

- ICRA ने वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में भारत की सकल मूल्य वर्धन (GVA) वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही में यह 6.8% थी। यह मजबूत राजकोषीय प्रोत्साहन के बावजूद आर्थिक गतिविधियों में मामूली नरमी का संकेत देता है। यह गिरावट पिछली तिमाही की तुलना में कुछ औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में धीमे विस्तार को दर्शाती है।

- रिपोर्ट में केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय (CapEx) में तीव्र वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है। वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में सकल पूंजीगत व्यय (CapEx) साल-दर-साल 52% बढ़कर ₹2.8 ट्रिलियन हो गया।

- इसकी तुलना में Q4FY25 में 33.4% की वृद्धि और Q1FY25 में 35% की गिरावट आई है, जो सरकार के नेतृत्व वाले बुनियादी ढांचे के खर्च में महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।

Key Points:-

(i) ICRA के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में GDP और GVA वृद्धि के बीच का अंतर 30 आधार अंक (bps) रहने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही के 62 आधार अंक से कम है। सकारात्मक अंतर यह संकेत देता है कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर (करों में से सब्सिडी घटाकर) GVA की तुलना में GDP वृद्धि को समर्थन देते रहेंगे।

(ii) एजेंसी ने निष्कर्ष निकाला कि भारत की

Q1FY26 आर्थिक गति मजबूत निर्यात मांग और सरकारी खर्च से प्रेरित होगी, लेकिन समग्र विकास पिछली तिमाही में प्राप्त 7%+ के स्तर से कम रहने की उम्मीद है।

(iii) यह दृष्टिकोण भारत की अल्पकालिक आर्थिक प्रगति का संतुलित किन्तु सतर्क मूल्यांकन प्रदान करता है।

MOUs and Agreement

1. सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स ने उन्नत रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स परियोजनाओं के लिए BEL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।



अगस्त 2025 में, बेंगलुरु स्थित सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (लिमिटेड) ने भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उन्नत रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स परियोजनाओं पर सहयोग करने के लिए रक्षा मंत्रालय के तहत एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSU) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

- BEL के निदेशक (विपणन) सुरेश कुमार के वी और सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (CMD) अप्पाराव वी मल्लावरपु के बीच BEL के कॉर्पोरेट कार्यालय में औपचारिक रूप से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस

समझौते से रक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मजबूत औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

- हस्ताक्षर समारोह में BEL के CMD मनोज जैन और सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष डॉ. विनोद चिप्पलकट्टी सहित प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, जिन्होंने दोनों संगठनों के लिए साझेदारी के रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डाला।

- यह सहयोग मुख्य रूप से उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध (EW) प्रणालियों, अगली पीढ़ी की रडार तकनीकों और भारत के सशस्त्र बलों को मजबूत बनाने हेतु सुरक्षित संचार समाधानों के विकास पर केंद्रित होगा। ये प्रणालियाँ भारत के रक्षा ढाँचे के आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

Key Points:-

(i) हस्ताक्षर समारोह में BEL के CMD मनोज जैन और सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष डॉ. विनोद चिप्पलकट्टी सहित प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, जिन्होंने दोनों संगठनों के लिए साझेदारी के रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डाला।

(ii) सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स और BEL का उद्देश्य भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स में नवाचार को गति प्रदान करना है। इस साझेदारी से रक्षा प्रणालियों के संवेदनशील क्षेत्र में स्वदेशी क्षमताओं में वृद्धि और विदेशी तकनीकों पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है।

(iii) यह समझौता ज्ञापन रक्षा मंत्रालय द्वारा अत्याधुनिक समाधानों के लिए सार्वजनिक और निजी उद्यमों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने, आधुनिक युद्ध परिदृश्यों में भारत की तैयारी सुनिश्चित करने और रक्षा कार्यों में तकनीकी श्रेष्ठता हासिल करने की व्यापक रणनीति को दर्शाता है।

App and Web Portal

1. दिल्ली सरकार ने एकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में 'दिल्ली मित्र' ऐप लॉन्च करने को मंजूरी दी।



अगस्त 2025 में, मुख्यमंत्री (CM) रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली मंत्रिमंडल ने 'दिल्ली मित्र' एप्लिकेशन के शुभारंभ को मंजूरी दी, जो एक एकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली (PGRS) है जिसे नागरिकों को शिकायत समाधान के लिए एकल-खिड़की मंच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- 'दिल्ली मित्र' ऐप, दिल्ली सरकार के विभागों, दिल्ली पुलिस, नगर निगमों (MCs) और दिल्ली छावनी बोर्ड सहित कई प्राधिकरणों से जुड़ी शिकायतों के लिए वन-स्टॉप प्लेटफ़ॉर्म के रूप में काम करेगा। यह एकीकरण प्रणालियों के दोहराव को समाप्त करता है और नागरिकों के लिए शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करता है।

- दिल्ली के निवासी चार माध्यमों से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे: एक समर्पित वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप सेवाएं और कॉल सेंटर सुविधा

- इसके अतिरिक्त, सरकारी कार्यालयों में प्रस्तुत हस्तलिखित शिकायतों को स्कैन किया जाएगा, डिजिटाइज़ किया जाएगा और सिस्टम में अपलोड किया जाएगा, जिससे ऑफलाइन प्रस्तुतियाँ पसंद

करने वाले नागरिकों के लिए समावेशिता सुनिश्चित होगी।

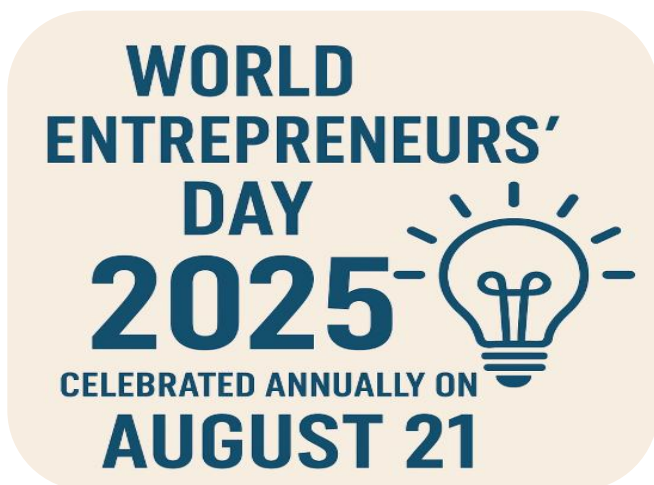
Key Points:-

(i) जवाबदेही को मज़बूत करने के लिए, सरकार शिकायतों की निगरानी और उनके समाधान में तेज़ी लाने के लिए हर विभाग में नोडल अधिकारी नियुक्त करेगी। लोक शिकायत अधिकारी हर बुधवार को नागरिकों के साथ साप्ताहिक जनसभाएँ भी आयोजित करेंगे, जिससे प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित होगा।

(ii) इस डिजिटल-प्रथम PGRS का शुभारंभ दिल्ली सरकार के पारदर्शिता, दक्षता और नागरिक-केंद्रित शासन पर केंद्रित रुख को दर्शाता है। कई एजेंसियों को एक मंच पर एकीकृत करके, इस पहल से देरी में उल्लेखनीय कमी आने, निगरानी में सुधार होने और एक उत्तरदायी सरकारी सेवा वितरण तंत्र के निर्माण की उम्मीद है।

IMPORTANT DAYS

1. विश्व उद्यमी दिवस 2025 प्रतिवर्ष 21 अगस्त को मनाया गया।



21 अगस्त, 2025 को, दुनिया भर में विश्व उद्यमी दिवस मनाया जाएगा, जो दुनिया भर के उद्यमियों की दूरदर्शिता, जोखिम उठाने की क्षमता और परिवर्तनकारी प्रभाव को मान्यता देने वाला एक

समर्पित अवसर है। साहस, नवाचार और आर्थिक योगदान के सम्मान में स्थापित इस दिवस का उद्देश्य भविष्य के परिवर्तनकर्ताओं को प्रेरित करना है।

• हर साल 21 अगस्त को मनाया जाने वाला यह दिन नासा के उड़ान निदेशक जीन क्रांज़ के जन्मदिन के साथ मेल खाता है—जो दूरदर्शी नेतृत्व का प्रतीक है। यह अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण, रोज़गार सृजन और सामाजिक प्रगति को प्रेरित करने में उद्यमिता की भूमिका को रेखांकित करता है।

• विश्व उद्यमी दिवस विभिन्न उद्योगों के संस्थापकों के साहस, रचनात्मकता और दृढ़ संकल्प को उजागर करता है। यह उद्यमिता के महत्व के बारे में व्यापक जागरूकता को बढ़ावा देता है और व्यक्तियों को अपने व्यावसायिक सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे भावी पीढ़ियों के लिए उद्यमशीलता की मानसिकता का पोषण होता है।

• उद्यमी नवाचार और आर्थिक विकास के प्रमुख चालक हैं। वे रोज़गार सृजन करते हैं, क्रांतिकारी तकनीकों का परिचय देते हैं और अर्थव्यवस्थाओं को फलने-फूलने में मदद करते हैं। तेज़ी से बढ़ते बाज़ारों में, स्टार्टअप और छोटे व्यवसाय अब क्षेत्रीय सकल घरेलू उत्पाद और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ बन गए हैं।

Key Points:-

(i) इस वर्ष का फोकस (हालांकि आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया गया है) स्थिरता, समावेशिता और डिजिटल परिवर्तन पर केंद्रित है। यह प्रभाव-संचालित उद्यमिता पर प्रकाश डालता है—ऐसे उद्यम जो लाभ के साथ-साथ सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्य को भी प्राथमिकता देते हैं।

(ii) इन आयोजनों में हैकार्थॉन, स्टार्टअप पिच सत्र, कार्यशालाएँ और नेटवर्किंग शिखर सम्मेलन जैसे वैश्विक और स्थानीय कार्यक्रम शामिल हैं।

विश्वविद्यालयों से लेकर व्यावसायिक केंद्रों तक, इन गतिविधियों का उद्देश्य मार्गदर्शन, शिक्षा और अग्रणी लोगों की सार्वजनिक मान्यता के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

2. विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है।

WORLD SENIOR CITIZENS' DAY

is observed globally on August 21



विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस हर साल 21 अगस्त को दुनिया भर में वृद्धजनों के अमूल्य योगदान को मान्यता देने और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसकी घोषणा सबसे पहले 1988 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने की थी, और बाद में इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया।

- राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 19 अगस्त, 1988 को घोषणापत्र संख्या 5847 जारी करके 21 अगस्त को अमेरिका में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में स्थापित किया। बाद में दिसंबर 1990 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को मान्यता दी और 1991 से इसे विश्व स्तर पर मनाया जाने लगा।

- इस दिवस का उद्देश्य वृद्धावस्था से संबंधित मुद्दों जैसे गिरते स्वास्थ्य, वृद्धों के साथ दुर्व्यवहार और सामाजिक बहिष्कार को उजागर करना है। यह परिवारों, समुदायों और राष्ट्रों के प्रति उनके

आजीवन योगदान का जश्र मनाते हुए वृद्ध नागरिकों के सम्मान को बढ़ावा देने पर ज़ोर देता है।

- जबकि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस (21 अगस्त) की उत्पत्ति अमेरिका से हुई है और इसे अंतराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, संयुक्त राष्ट्र भी 1 अक्टूबर को अंतराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाता है, जिसकी स्थापना 1990 में संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव 45/106 द्वारा की गई थी।

Key Points:-

(i) संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, दुनिया भर में वृद्धजनों की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। 2050 तक, वैश्विक वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 1.5 अरब से ज़्यादा होने का अनुमान है, जिनमें से दो-तिहाई विकासशील देशों में रहेंगे—जो समावेशी नीतियों की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है।

(ii) समुदाय पुरस्कार समारोहों, सामाजिक समारोहों, स्थानीय जागरूकता अभियानों और स्वास्थ्य सेवा अभियानों जैसे आयोजनों के माध्यम से इस दिन को मनाते हैं। लोग भी बुजुर्गों के साथ अच्छा समय बिताने, वृद्धाश्रमों में स्वयंसेवा करने और बेहतर सेवाओं और सम्मान की वकालत करने के अवसरों का लाभ उठाते हैं।

OBITUARY

1. कॉट इन प्रोविडेंस के 'दुनिया के सबसे अच्छे न्यायाधीश' फ्रैंक कैप्रियो का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया।



न्यायाधीश फ्रैंक कैप्रियो, जिन्हें प्यार से "दुनिया के सबसे अच्छे न्यायाधीश" के रूप में जाना जाता है और वायरल कोर्टरूम श्रृंखला कॉट इन प्रोविडेंस के स्टार, अग्राशय के कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद 88 वर्ष की आयु में 20 अगस्त, 2025 को निधन हो गया।

- 1985 से 2023 तक प्रोविडेंस म्यूनिसिपल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में लगभग चार दशकों तक सेवा करते हुए, कैप्रियो ने मामूली अपराध के मामलों की सहानुभूति, निष्पक्षता और हास्य की एक लोक-सुलभ भावना के साथ अध्यक्षता करने के लिए वैश्विक प्रशंसा प्राप्त की, जिसमें सजा की तुलना में समझ पर जोर दिया गया।

- टीवी सीरीज़ कॉट इन प्रोविडेंस के ज़रिए उनका कोर्टरूम एक सांस्कृतिक परिघटना बन गया। 2000 में स्थानीय स्तर पर शुरू हुआ और 2018 से प्रसारित, इस शो को — जो अपने दिल को छू लेने वाले फैसलों और कैप्रियो के मानवीय दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है — कई डेटाईम एमी नामांकन मिले और ऑनलाइन अरबों व्यूज़ मिले।

Key Points:-

(i) अपने निधन से कुछ घंटे पहले, जज फ्रैंक कैप्रियो ने अस्पताल के बिस्तर से इंस्टाग्राम पर एक बेहद मार्मिक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने अपने अनुयायियों से उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखने का अनुरोध किया था—जो उनकी विनम्रता और आस्था

का प्रमाण था। प्रशंसकों और सरकारी अधिकारियों, दोनों ने ही उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, रोड आइलैंड के गवर्नर डैन मैकी ने फ्रैंक कैप्रियो के सम्मान में झंडे आधे झुकाने का आदेश दिया।

(ii) कैप्रियो की विरासत उनके कानूनी फैसलों से कहीं आगे तक फैली हुई है। अपनी गर्मजोशी, विनम्रता और लोगों की भलाई में अटूट विश्वास के लिए प्रिय, उन्होंने अपने न्यायिक कार्यों और एक वायरल इंटरनेट हस्ती के रूप में लाखों लोगों को प्रभावित किया। उनके निधन ने एक अद्वितीय करुणामयी करियर का अंत कर दिया।

Static GK

Exim Bank of India	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक: सुश्री हर्षा बांगर	मुख्यालय: मुंबई
Ministry of Communications (MoC)	केंद्रीय मंत्री: ज्योतिरादित्य सिंधिया	मुख्यालय: नई दिल्ली
Uttar Pradesh	मुख्यमंत्री: योगी आदित्यनाथ	राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल
Saudi Arabia	राजधानी: रियाद	मुद्रा: सऊदी रियाल
ICRA Limited	MD & CEO : रामनाथ कृष्णन	मुख्यालय : गुरुग्राम, हरियाणा